
Q. Discuss the concept of de-dollarisation and its implications on global trade and economic sovereignty.

De-dollarisation refers to the process by which countries reduce their reliance on the US dollar in international trade and finance. The countries thus, shift to alternative currencies like the euro, yuan, or local currencies, and explore digital assets like cryptocurrencies to reduce dependence on the dollar. Historically, the US dollar has been the world's reserve currency, but recent trends suggest a growing movement toward alternatives, driven by both economic and geopolitical factors.

Countries like China, Russia, and the BRICS nations are actively pursuing de-dollarisation strategies to reduce their reliance on the US dollar. China, through its Belt and Road Initiative (BRI), is promoting the use of the yuan by entering into yuan-based trade agreements, thus expanding its global influence and reducing dependence on the dollar. Russia, in response to US sanctions, has been exploring the use of the rupee-rouble exchange to bypass dollar transactions in trade with India. Meanwhile, the BRICS nations are discussing the possibility of a shared currency to facilitate intra-group trade without relying on the US dollar. These efforts highlight the broader movement toward economic sovereignty and the desire to mitigate the risks associated with dollar dominance in global finance.

Implications on Global Trade:

- **Diversification of Currency Use:** Reduces reliance on the dollar, with countries engaging in trade agreements in local currencies
- **Lower Transaction Costs:** Bilateral trade in non-dollar currencies eliminates the need for conversion, reducing costs
- **New Financial Infrastructure:** Systems like China's CIPS aim to bypass dollar-dominated systems like SWIFT, promoting alternate payment systems.

Implications on Economic Sovereignty:

- **Increased Economic Independence:** Countries regain control over their financial systems, avoiding sanctions and dollar volatility.
- **Protection from US Economic Leverage:** Countries gain a safeguard against economic coercion tied to dollar dominance.

However, de-dollarisation faces significant hurdles. One of the primary challenges to de-dollarisation is the need for substantial **infrastructure investment**. Countries must establish alternative financial systems and payment platforms, requiring significant resources. For instance, China's CIPS system, designed to bypass SWIFT, highlights the type of infrastructure needed to reduce reliance on dollar-dominated systems. Another challenge is **geopolitical resistance**, as the US dollar continues to dominate global institutions like the IMF, SWIFT, and the World Bank.

De-dollarisation is a gradual, complex process driven by the desire for greater economic sovereignty and the rise of alternatives like cryptocurrencies and bilateral trade in local currencies. While countries like China, Russia, and the BRICS nations are making strides, the challenge remains in overcoming the infrastructural and geopolitical obstacles to fully transition away from the US dollar.

प्रश्न: डी-डॉलरीकरण की अवधारणा और वैश्विक व्यापार और आर्थिक संप्रभुता पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

डी-डॉलराइजेशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करते हैं। इस प्रकार, देश यूरो, युआन या स्थानीय मुद्राओं जैसी वैकल्पिक मुद्राओं की ओर रुख करते हैं, और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए क्रिप्टोकॉरेंसी जैसी डिजिटल परिसंपत्तियों की ओर ध्यान लगाते हैं। ऐतिहासिक रूप से, अमेरिकी डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा रही है, लेकिन हाल के रुझान आर्थिक और भू-राजनीतिक दोनों कारकों से प्रेरित होकर विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं।

चीन, रूस और ब्रिक्स राष्ट्र जैसे देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सक्रिय रूप से डी-डॉलरीकरण रणनीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। चीन, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से, युआन-आधारित व्यापार समझौतों में प्रवेश करके युआन के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है, इस प्रकार अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार कर रहा है और डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है। रूस, अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में, भारत के साथ व्यापार में डॉलर के लेन-देन को दरकिनार कर रुपया-रूबल विनिमय के उपयोग पर जोर दे रहा है। इस बीच, ब्रिक्स राष्ट्र अमेरिकी डॉलर पर निर्भर हुए बिना अंतर-समूह व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक साझा मुद्रा की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। ये प्रयास आर्थिक संप्रभुता को बढ़ाने और वैश्विक वित्त में डॉलर के प्रभुत्व से जुड़े जोखिमों को कम करने की इच्छा को उजागर करते हैं।

वैश्विक व्यापार पर प्रभाव:

- **मुद्रा उपयोग का विविधीकरण:** डॉलर पर निर्भरता कम होती है, क्योंकि देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते करते हैं।
- **कम लेनदेन लागत:** गैर-डॉलर मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार रूपांतरण की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे लागत कम हो जाती है।
- **नया वित्तीय बुनियादी ढांचा:** चीन की CIPS जैसी प्रणालियों का उद्देश्य SWIFT जैसी डॉलर-प्रधान प्रणालियों को दरकिनार करना है, जिससे वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा मिलता है।

आर्थिक संप्रभुता पर प्रभाव:

- **आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि:** देश प्रतिबंधों और डॉलर की अस्थिरता से बचते हुए अपनी वित्तीय प्रणालियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं।
- **अमेरिकी आर्थिक उत्तोलन से सुरक्षा:** देशों को डॉलर के प्रभुत्व से जुड़ी आर्थिक जबरदस्ती के खिलाफ सुरक्षा मिलती है।

हालांकि, डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया से जुड़ी बाधाएं भी हैं। डी-डॉलराइजेशन की प्राथमिक चुनौतियों में से एक पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता है। देशों को वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली और भुगतान प्लेटफॉर्म स्थापित करने होंगे, जिसके लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, चीन की CIPS प्रणाली, जिसे SWIFT को बायपास करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, डॉलर-प्रधान प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के प्रकार को उजागर करती है। एक अन्य चुनौती भू-राजनीतिक प्रतिरोध है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर का IMF, SWIFT और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं पर प्रभुत्व रहा है।

डी-डॉलरीकरण एक क्रमिक, जटिल प्रक्रिया है जो आर्थिक संप्रभुता की इच्छा और क्रिप्टोकॉरेंसी और स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार जैसे विकल्पों के उदय से प्रेरित है। जबकि चीन, रूस और ब्रिक्स राष्ट्र जैसे देश इस संदर्भ में प्रगति कर रहे हैं, अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह से त्यागने के लिए बुनियादी ढांचे और भू-राजनीतिक बाधाओं को दूर करने की चुनौती अभी भी बनी हुई है।